

पीपीपी मॉडल पर कृषि प्रसंस्करण इकाइयों को मिलेगा बढ़ावा

मुख्यमंत्री ने दिए ज्यादा से ज्यादा मंडियों को ई नाम से जोड़ने के निर्देश
राज्य कृषि उत्पादन मंडी परिषद के संचालक मंडल की 172वीं बैठक

अमर उजाला ब्यूरो

लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शुक्रवार को राज्य कृषि उत्पादन मंडी परिषद के संचालक मंडल की 172वीं बैठक को संबोधित किया। उन्होंने पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप (पीपीपी) मॉडल में कृषि प्रसंस्करण इकाइयों को बढ़ावा देने का निर्देश दिया। मुख्यमंत्री ने अधिकाधिक मंडियों को ई नाम (राष्ट्रीय कृषि बाजार) प्लेटफॉर्म से जोड़ने पर भी जोर दिया।

बैठक में वर्ष 2026-27 के लिए 3025.49 करोड़ रुपये के बजट को स्वीकृति मिली। किसान कल्याण, कृषि विपणन और मंडी व्यवस्था से जुड़े अनेक प्रस्तावों को भी मंजूरी दी गई। मुख्यमंत्री ने प्रदेश की मंडियों के आधुनिकीकरण और पुनरोद्धार के निर्देश दिए। उन्होंने मंडियों को आधुनिक सुविधाओं से लैस करने को कहा। इससे किसानों को बेहतर



■ **मंडी की आय में वृद्धि** : बैठक में वित्तीय वर्ष 2025-26 के संशोधित आय-व्यय अनुमान अनुमोदित हुए। वर्ष 2026-27 के लिए 2228.59 करोड़ रुपये की अनुमानित प्राप्तियां स्वीकृत हुईं। व्यव प्रावधान 3025.49 करोड़ रुपये को भी मंजूरी मिली। विभागीय अधिकारियों ने मंडी समितियों की आय में वृद्धि दर्ज की। आय वर्ष 2024-25 के 1991.33 करोड़ रुपये से बढ़कर वर्ष 2025-26 में 2305.80 करोड़ रुपये हो गई, जो 15.79 प्रतिशत की उल्लेखनीय वृद्धि है।

और पारदर्शी विपणन व्यवस्था उपलब्ध हो सकेगी। पेयजल, स्वच्छता और प्रकाश व्यवस्था सहित मूलभूत सुविधाओं को सुदृढ़ करने पर विशेष जोर दिया गया। मुख्यमंत्री ने मंडी स्थलों में पीपीपी मॉडल पर कृषि उपज प्रसंस्करण इकाइयों की स्थापना को प्रोत्साहित करने को कहा। इसके लिए नियमों को अधिक व्यावहारिक और निवेश अनुकूल बनाने के निर्देश दिए गए। संचालक मंडल ने मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना सहायता योजना की

अवधि बढ़ाई। मुख्यमंत्री खेत-खलिहान अग्निकांड दुर्घटना सहायता योजना की अवधि भी 1 जुलाई 2025 से 30 जून 2030 तक बढ़ाई गई। वर्ष 2026-27 के बजट में इन दोनों योजनाओं के लिए 30 करोड़ रुपये का प्रावधान है। मूल्य समर्थन योजना (पीएसएस) के तहत दलहन और तिलहन की खरीद व्यवस्था को प्रभावी बनाने की मंजूरी मिली। इसके लिए विभिन्न सहकारी संस्थाओं को व्याजमुक्त कार्यशील पूंजी उपलब्ध कराई जाएगी।

85 देशों के 550 खरीदार लेंगे हिस्सा

लखनऊ। उत्तर प्रदेश को वैश्विक व्यापार, विनिर्माण और निर्यात का प्रमुख केंद्र बनाने के उद्देश्य से उत्तर प्रदेश इंटरनेशनल ट्रेड शो (यूपीआईटीएस)-2026 का चौथा संस्करण 25 से 29 सितंबर तक ग्रेटर नोएडा के इंडिया एक्सपो सेंटर एंड मार्ट में आयोजित होगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शुक्रवार को तैयारियों की समीक्षा करते हुए कहा कि यह आयोजन प्रदेश की औद्योगिक क्षमता, नवाचार और निर्यात सामर्थ्य को दुनिया के सामने प्रस्तुत करने का सबसे प्रभावी मंच बनेगा तथा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 'मेक इन इंडिया' और 'मेक फॉर द वर्ल्ड' के विजन को गति देगा।

'यूपी फॉर ग्लोबल ग्रोथ: इनोवेशन, मैनुफैक्चरिंग एंड एक्सपोर्ट्स' थीम पर आधारित ट्रेड शो में 2,400 से अधिक प्रदर्शक, डेढ़ लाख बी2बी खरीदार, साढ़े

यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो : 25 से 29 सितंबर तक ग्रेटर नोएडा में आयोजन, वैश्विक व्यापार हब बनने की ओर बड़ा कदम

सरदार पटेल योजना में बीबीजी समूह टीसीएस और हीरानंदानी समूह की रुचि

बैठक में सरदार वल्लभभाई पटेल रोजगार एवं औद्योगिक क्षेत्र विकास योजना की भी समीक्षा हुई। अधिकारियों ने बताया कि बीबीजी समूह, टीसीएस और हीरानंदानी समूह ने रुचि दिखाई है। 19 जिलों में 1320 एकड़ भूमि चिह्नित की जा चुकी है और पहले चरण में 17 केंद्र विकसित किए जाएंगे। नौ क्षेत्रीय हब एंड स्पोक मॉडल के माध्यम से प्रतिवर्ष 10 लाख युवाओं को कौशल प्रशिक्षण तथा 80 प्रतिशत प्रशिक्षित युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया है।

चार लाख से अधिक आगंतुक और 85 देशों के 550 से अधिक अंतरराष्ट्रीय खरीदारों की भागीदारी का लक्ष्य है। 4,000 से अधिक एमओयू, 3,200 करोड़ रुपये के प्रस्तावित निवेश समझौते तथा 13,500 करोड़ रुपये से अधिक की व्यावसायिक पूछताछ की उम्मीद है। ओडीओपी, एमएसएमई, इलेक्ट्रॉनिक्स, रक्षा, कृषि, पर्यटन,

स्टार्टअप, खाद्य प्रसंस्करण, अश्वय ऊर्जा, ईवी, स्वास्थ्य, हस्तशिल्प और वस्त्र सहित अनेक क्षेत्रों का प्रदर्शन होगा। कृत्रिम बुद्धिमत्ता, साइबर सुरक्षा, ई-कॉमर्स, बैंकिंग, मुक्त व्यापार समझौते और एमएसएमई पर नॉलेज सेशन आयोजित किए जाएंगे, जबकि सांस्कृतिक प्रस्तुतियां भी आकर्षण का केंद्र रहेंगी। ब्यूरो

संस्थान विज्ञान पर प्रयोग प्रकाश विज्ञान की शक्ति अक्षय परमाण्वीय शक्ति से 10 प्रतिशत